(ख) क्या भारी संख्या में यात्री प्रति दिन बसों में यात्रा करते हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अगर बसों की वर्तमान क्षमता में वृद्धि नहीं की जाती है, तो मार्च, 1978 तक सात लाख अतिरिक्त यात्रियों की बसें सुलभ नहीं होंगी; और

(घ) यदि हां, तो कितनी और बस चलाने का प्रस्ताव है और वे कब तक चलाई जायेंगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां। अक्तूबर मास, 1977 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम ने औसतन प्रतिदिन 1558 बसें चलाईं। उसी अवधि के दौरान किलोमीटर दूरी पर चलने वाली प्राइवेट बसों की संख्या 300 थी । इसके अलावा दिल्ली परिवहन निगम के पास अपनी "प्रशासनिक तथा परिचालनात्मक नियंत्रण प्रभार" योजना के अन्तर्गत 123 मानक आकार तथा 253 मिनी बसें थीं ।

(ख) अक्तूबर, 1977 के दौरान औसतन किलोमीटर योजना के अन्तर्गत लगायी गयी प्राइवेट बसों सहित दिल्ली परिवहन निगम की बसों में प्रतिदिन 21.50 लाख यात्रियों ने सफर किया। इसमें ए०ओ० सी० सी० योजना के अन्तर्गत परिचालित दिल्ली परिवहन निगम परिचालन के अन्तर्गत प्राइवेट बसों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या शामिल नहीं है ।

(ग) यह स्थिति टाऊन तथा कन्ट्री प्लानिंग संगठन द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार होगी ।

(घ) निगम का मार्च, 1978 के अन्त तक 162 नई बसें खरीदने का प्रस्ताव है। इससे राजधानी में मौजूदा परिचालित निजी बसों के अतिरिक्त 500 निजी बसों को लगा कर बस सेवा को उन्नत करने का भी निश्चय किया है इसके अलावा 280 बसों को वापिस सड़क पर लाने के लिए, जो कि कर्मशाला की मरम्मत के कारण रुकी रही, एक तुरन्त कार्यक्रम आरम्भ किया है । इससे निगम की मार्च, 1978 के अन्त तक सड़क पर बसों की संख्या बढ़ कर 2344 हो जायेगी तथा प्रतिदिन 26 लाख यात्री सफर कर सकेंगे । इसके अलावा दिल्ली परिवहन निगम की ए०ओ०सी० सी० योजना के अन्तर्गत परिचालित मानक आकार तथा मिनी बसों द्वारा प्रतिदिन लगभग 3 लाख यात्रियों के सफर करने की संभावना है । इस प्रकार पूरी आवश्यकताओं को पूरा करना संभव हो सकेगा ।

Adverse effect of Import of Power Generation Equipment on BHEL

465. SHRI D. D. DESAI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the criticism that import of power generation equipment will adversely affect the BHEL ;

(b) if so, Government's reaction thereto; and

(c) the comparative order book position of BHEL, as against its annual capacity for the next five years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (KUMARI ABHA MAITI) : (a) Yes, Sir.

(b) There is a ban on the import of power generation equipment. Relaxation from it is granted only in those few cases where the equipment is not within the manufacturing range of BHEL or where the deliveries are unduly long.

(C) *Comparative Statement of order book position indicating the scheduled supply of power generating equipment for 5 years*

THERMAL SETS					HYDRO SETS					
Existing Annual installed capacity					Existing Annual installed capacity					
Sets of 210 MW 7 sets. Sets of 120 MW 3 sets. Sets of 110 MW 7 sets.					BHEL has a total installed capacity to manufacture around 1000 MW of hydro sets of various ratings. They constitute around 15 to 20 numbers on an average.					
ORDER BOOK POSITION					ORDER BOOK POSITION					
Rating (MW)	1977-1978	1978-1979	1979-1980	1980-4981	1977-1978	1978-1979	1979-1980	1980-1981	1981-1982	1982-1983
210	7	5	5	5						
120	1	1	..	..	19	11	8	6	1	Nil.
110	1	2		..						
Rating (MW)	1981-1982	1982-1983								
210		..								
120	..									
110	..	..								

बेतवा नदी पर नोटघाट पुल

466. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेतवा नदी पर नोटघाट पुल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय सरकार द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सरकार द्वारा खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पुल पर बेरियल लगा दिया है और वह चुंगी कर की वसूली कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार वसूल की गयी धनराशि को तीनों सरकारों में बांटा जाएगा और इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (घ). बेतवा नदी पर नोटघाट पुल उस राज्य सड़क पर है जो कुछ उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश में पड़ती है और जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया । परन्तु, दोनों राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने पुल की लागत के कुछ भाग के लिए केन्द्रीय सड़क निधि (साधारण) से 8.90 लाख रुपये का सहायता अनुदान दिया और शेष 22.44 लाख रुपये उत्तर प्रदेश